



117

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

१९५७-२-१-१७

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

८५८८०

सन 2017

वी ४१८-८८६३

द्वारा आज दि १९/११/१७

प्रस्तुत

१. सी० ई० फांसिस उम्र ७० वर्ष तनय स्व० श्री पी० ई० फांसिस

निवासी सी-२५१, महेश नगर, लाल कोठी गांधी नगर जयपुर

बालक आँख कोटि निवासी सी-२५१, महेश नगर, लाल कोठी गांधी नगर जयपुर  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर राजस्थान" - ३०२०१५

२. एस० डबल० फांसिस उम्र ६० वर्ष तनय स्व० श्री पी० ई० फांसिस

निवासी काइस्ट नगर, हरहुआ, दादूपुर, वाराणसी, उ०प्र०-२२१००३

आवेदक क्रमांक १ व २ द्वारा मुख्तायार भाई एम० डी० फांसिस

उम्र ६७ वर्ष तनय स्व० श्री पी० ई० फांसिस निवासी वार्ड नंबर

९६ महात्मा गांधी नगर, डी० सी० एम०, अजमेर रोड जयपुर "राजस्थान"

३. एम० डी० फांसिस उम्र ६७ वर्ष तनय स्व० श्री पी० ई० फांसिस

निवासी वार्ड नंबर ९६ महात्मा गांधी नगर, डी० सी० एम०, अजमेर रोड

जयपुर "राजस्थान"

.....आवेदकगण

बनाम

१. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र०

२. फांसिस पुत्र श्री ई० फांसिस निवासी नौगांव तहसील नौगांव - फारमस्य पड़ाभ०

जिला छतरपुर म०प्र०

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा ५१ म०प्र० भ० राजस्व संहिता १९५९

बावत आदेश दिनांक १९/१२/१६ पारित अंतर्गत प्रकरण क्रमांक

निगरानी ३५२६/१/२०१६ जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक २

का नाम राजस्व खसरा अभिलेख में दर्ज किये जाने को आदेश

दिया गया है के स्थान पर आवेदकगण का नाम राजस्व

अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन

महोदय,

आवेदकगण श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

*M. J. Francis*

क्रमशः २

प्रकरण कमांक रिव्यू 257-एक / 17

जिला - छतरपुर

रथान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों  
आदि के  
हस्ताक्षर

४-२-१७

आवेदक अभिभाषक श्री आर०एस० सेंगर एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3526-एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण मृतक श्री पी०ई० फांसिस के पुत्रगण होकर उनके वैद्य वारिश, विधिक उत्तराधिकारी हैं, आवेदकगण आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार हैं। यह भी तर्क दिया कि वर्णित संपत्ति भू-खण्ड कमांक 01/59 के 5600 वर्ग मीटर का पट्टा सन 1954 में आवेदकगण के पिता को नियमानुसार दिया गया था, जिस पर वे जीवन पर्यन्त काबिज दखिल रहे हैं और उनकी मृत्यु उपरांत से आवेदकगण उक्त भू-खण्ड के आधिपत्य में होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इस कारण पिता की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण का नाम खसरा अभिलेख में दर्ज किया न्यायपूर्ण है। कथित संपत्ति के मालिक आवेदकगण है परन्तु अनावेदक कमांक 2 जिसका कि मृतक स्व० श्री पी०ई०फांसिस की संपत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं है व न ही उसका कथित संपत्ति को सरोकार है आवेदकगण के पिता द्वारा अनावेदक कमांक 2 अथवा अन्य किसी को अपनी संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की गई है फिर भी अनावेदकगण ने मृतक के वारसान

आवेदकगण को छुपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संपत्ति खसरा क्रमांक 1/59 रकवा 0.559 हे० भूमि पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश सही तथ्यों को छुपाते हुये प्राप्त किया है। आवेदकगण वादोक्त भूमि के आधिपत्यधारी है एवं आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है परन्तु फिर भी अनावेदक क्रमांक द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुये अपने नाम से जो आदेश प्राप्त किया है वह किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। जबकि वादोक्त भू-खण्ड से अनावेदक क्रमांक 2 का कोई हित अथवा वास्ता नहीं है इस वजह से पारित आदेश को पुनर्विलोकन में लिया जाकर अनावेदक क्रमांक 2 के नाम के स्थान पर आवेदकगण का नाम खसरा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिया जाना न्यायपूर्ण है। अतः पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया।

3— अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि निगरानी में जो आदेश पारित किया है वह विधि अनुसार पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया।

4— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि दिनांक 19-7-1954 को डिप्टी कलेक्टर छतरपुर द्वारा भूखण्ड क्रमांक 1/59 में 5600 वर्गमीटर का पट्टा मृतक पी०ई० फांसिस था जिसके पश्चात कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 74/अ-20/1/83-84 में पारित आदेश दिनांक 31-1-85 द्वारा उक्त पट्टा आगामी 30 वर्ष के लिये जारी किया गया। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत

1/4

OM

दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी पी0ई0 फांसिस की जिनकी मृत्यु वर्ष 03-4-1991 में हुई। मृत्यु उपरांत अनावेदक क्रमांक 2 फांसिस द्वारा मृतक पी0ई0 फांसिस की वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण चाहा जिसपर तहसीलदार नौगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-5-2012 को निरस्त किया गया। मृतक पी0ई0 फांसिस के तीन वैद्य वारिसान थे जिनकी उक्त वसीयत की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी फिर उक्त वसीयत मृतक पी0ई0 फांसिस द्वारा कब और कहाँ लिखी गई तथा मृत्यु वर्ष 1991 के पश्चात वर्ष 2012 में अर्थात् 21 वर्ष बाद वसीयत नामांतरण हेतु प्रस्तुत करना अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होती है। यहां यह भी विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पट्टाग्रहिता के वैद्य वारिस होते हुये उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति जिसका उनसे कोई संबंध न हो, उसे वसीयत क्यों की गई। चूंकि तहसीलदार द्वारा भी वसीयत के आधार पर अनावेदक क्रमांक 2 जो कि फर्जी नाम फांसिस का सहारा लेकर नामांतरण चाह रहा था, को अपने आदेश दिनांक 15-5-12 से निरस्त किया है। वसीयत भी किसी न्यायालय में प्रमाणित नहीं हुई है। फिर भी इस न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 जो कि मृतक पी0ई0 फांसिस का वारिस नहीं है फिर भी उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निगरानी में आदेश देने में त्रुटि हुई है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मृतक पी0ई0 फांसिस का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदकगण के आधार कार्ड, एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ही मृतक पी0ई0 फांसिस के असल वारिस हैं और उन्हें ही मृतक पी0ई0 फांसिस के भूमि पर मृत्यु उपरांत नामांतरण के अधिकार प्राप्त हैं। अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा एक जैसे नाम होने का सहारा लेकर इस न्यायालय को गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर

गुमराह किया है। जहां तक अनावेदक द्वारा लिये गये वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने तर्क का प्रश्न है चूंकि वसीयत 21 वर्ष प्रस्तुत करना ही अपने आप में संदिग्ध है इसलिए आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-12-16 निरस्त किया जाता है। आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

  
( एम.के. सिंह )

सदस्य,  
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

PK